समक्ष *माननीय एस. एस. सो* सोढ़ी, न्यायमूर्ति

चरण दास,-याचिकाकर्ता।

बनाम

सुरींदर कुमार और अन्य- प्रतिवादी।

***1991 की चुनाव* याचिका *संख्या* 5**

13 मई, 1992

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1955-एस. एस. 80, 81 और 83-कार्रवाई का कारण-सामग्री तथ्यों का प्रकटीकरण-अस्पष्ट और सामान्य आरोप- कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताया गया।

ये अभिनिर्धारित किया गया, याचिका को पढ़ने पर जो बात प्रमुखता से सामने आती है, वह यह है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में डाले गए वोटों के बारे में लगाए गए अस्पष्ट और सामान्य आरोपों को पहले लौटे उम्मीदवार के वोटों में शामिल किया जाता है और जब उस पर आपत्ति जताई जाती है, तो ऐसे वोटों को शामिल किया जाता है। अमान्य घोषित कर दिया गया. बेशक, ऐसे किसी भी अस्वीकृत वोटों का कोई रिकॉर्ड या नोट कभी नहीं रखा गया था। इसके अलावा और अधिक महत्वपूर्ण यह है कि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विवादित मतपत्रों की जांच के चरण में किसी भी गलत काम के दावे का पूर्ण अभाव है। कम से कम उस स्तर पर उम्मीदवारों या उनके एजेंटों को वोटों की जांच करने का अवसर देने से इनकार करने का कोई उल्लेख नहीं है। इन सबके अलावा, इस बात का कोई दावा नहीं है कि चुनाव के नतीजे कथित अनियमितताओं से प्रभावित हुए थे। इस निष्कर्ष से बच नहीं सकते कि याचिका कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताती है।

(अनुच्छेद 27 &28)

याचिकाकर्ता की ओर *से- अधिवक्ता रंजन लखनपाल,*

एस. सी. कपूर, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ मैसर्स राकेश नागपाल, अधिवक्ता और आशीष कपूर, *अधिवक्ता, प्रतिवादी की ओर से।*

निर्णय

एस. एस. सोढ़ी, न्यायमूर्ति

(1) यहाँ चुनौती है कि मतों की गिनती के दौरान हुई अनियमितताओं के आधार पर कैथल विधानसभा क्षेत्र से सुरिंदर कुमार के चुनाव को लेकर है। इस प्रकार चुनाव को रद्द करने और वोटों की दोबारा गिनती करने से राहत की मांग की गई।

(2) सफल उम्मीदवार सुरिंदर कुमार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी याचिकाकर्ता चरण दास को 437 मतों के अंतर से हराया। याचिकाकर्ता के 16,735 वोटों की तुलना में सुरिंदर कुमार को 17,190 वोट मिले।

(3) एक निर्विवाद शक्ति न्यायालय में निहित है कि वह मतों की पुनः गिनती का आदेश दे। इस तरह की शक्ति का उपयोग कब किया जा सकता है या किया जाना चाहिए, यह अब 21 जनवरी, 1992 को तय की गई 1991 की चुनाव याचिका 3 *(जगजीत सिंह* बनाम *धरम पाल सिंह और अन्य)* में इस न्यायालय के हालिया फैसले में देखे गए और चर्चा किए गए न्यायिक पूर्व निर्णय द्वारा अच्छी तरह से तय किया गया है।जैसा कि अभिनिर्धारित किया गया है, आवश्यक पूर्व शर्त भौतिक तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण *है जिस पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है ।इस निर्णय के* प्रासंगिक भाग को उद्धृत करने के लिए, "जैसा कि डॉ. जगजीत सिंह बनाम ज्ञानी कर्तार सिंह और अन्य * (1) में उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया है" अस्पष्ट या सामान्य आरोप कि वैध मतों को अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया था या अमान्य मतों को अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया था या अमान्य मतों को अनुचित रूप से स्वीकार कर लिया गया था, उस उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा जो धारा 83 (1) (ए), दिमाग में है। मतपेटियों के निरीक्षण के लिए किए गए आवेदन में महत्वपूर्ण तथ्य होना चाहिए जो न्यायाधीशाधिकरण को इस बात पर विचार करने में सक्षम बनाएगा कि न्यायाधीश के हित में मतपेटियों का निरीक्षण किया जाना चाहिए या नहीं। इस प्रश्न से निपटने में, मतपत्रों की गोपनीयता के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और यह हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अधिनियम के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों का उद्देश्य मतों की वैधता या अयोग्यता की जांच और उनकी उचित गिनती के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ मामलों में न्यायाधीश के उद्देश्य से न्यायाधीशाधिकरण के लिए यह आवश्यक हो जाएगा कि वह किसी पक्ष को मतपेटियों का निरीक्षण करने की अनुमति दे और किसी भी चुनाव में मतदाताओं द्वारा दिए गए मतों की अनुचित स्वीकृति या अनुचित अस्वीकृति के बारे में उनकी आपत्तियों पर विचार करे; लेकिन न्यायाधीश की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए, इस

बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि चुनाव याचिकाकर्ताओं को मतपेटियों में घूम-घूम कर या पूछताछ करने का मौका न मिले ताकि उनके इस दावे को सही ठहराया जा सके कि लौटे उम्मीदवार का चुनाव अमान्य है ।

(4) इसके अलावा, इस बात पर जोर दिया गया कि चुनाव संचालन नियमों के भाग-5 में निर्धारित प्रासंगिक नियमों की योजना के अनुसार,1961.“— एक पराजित उम्मीदवार के पास मतदान पत्रों की गिनती से पहले उनकी जांच करने का पर्याप्त अवसर होता है, और यदि उसके या उसके चुनाव एजेंट द्वारा उठाई गई आपत्तियों को अनुचित तरीके से खारिज कर दिया गया है, तो वह अपने द्वारा उठाई गई आपत्तियों और उन मतदान पत्रों की प्रकृति को ठीक से जानता है जिनसे वे आपत्तियां संबंधित हैं। इसी पृष्ठभूमि में मतपेटियों के निरीक्षण के लिए की गई याचिकाओं पर अधिनियम की धारा 83 (1) लागू की जानी है। इस तरह के आवेदन में भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए।”

(5) न्यायालय ने उन सुरक्षा उपायों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जो आचरण के भाग-5 में निर्धारित किए गए हैं। चुनाव नियम, 1961, जिसकी व्यापक विशेषताओं को इस प्रकार इंगित किया गया था, "-आर. 53 उम्मीदवारों के तहत, उनके चुनाव एजेंटों या गिनती एजेंटों को वोटों की गिनती के लिए निर्धारित स्थान पर प्रवेश दिया जाता है। नियम-54 मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है।नियम 55 मतपेटियों की जांच और उन्हें खोलने से संबंधित है, गिनती की मेज पर मतपेटिका खोलने से पहले, उस मेज पर मौजूद गिनती एजेंटों को कागजी मुहर या ऐसी अन्य मुहर का निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी जो उस पर चिपकाई गई हो और खुद को संतुष्ट करने के लिए कि वह बरकरार है।निर्वाचन अधिकारी को स्वयं इस बात का ध्यान रखना होता है कि किसी भी मतपेटी के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। यदि मतपेटियों में किसी भी तरह की

छेड़छाड़ का खुलासा किया जाता है, तो निर्वाचन अधिकारी को नियम. 58 के तहत कार्रवाई करनी होती है। नियम-56 में मतपत्रों की जांच और अस्वीकृति का प्रावधान है।आर. 56 (1) में कहा गया है कि प्रत्येक मतपेटी से निकाले गए मतपत्रों को सुविधाजनक बंडलों में व्यवस्थित किया जाएगा और उनकी जांच की जाएगी।फिर आपत्तियों को उप-नियम (2) द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है और नियम. 56 (2) के अन्य उपखंडों के प्रावधानों के अनुसार निपटा जाता है।इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नियम 56 की योजना यह है कि प्रत्येक मतपत्र की जांच गणना एजेंट द्वारा की जा सकती है और यदि चुनाव एजेंट को लगता है कि एक वैध आपत्ति उठाई जा सकती है तो इसके संबंध में आपत्तियां उठाई जा सकती हैं।इन आपत्तियों की जांच करने और नियम. 56 के अनुसार निपटाने के बाद ही मतों की गिनती का चरण आता है। गिनती पूरी होने के बाद भी, एक उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट के लिए यह खुला है कि वह पहले से ही गिने गए सभी या किसी भी मतपत्र की फिर से गिनती के लिए निर्वाचन अधिकारी को लिखित रूप में आवेदन कर सकता है, जिसमें उन आधारों को बताया जाए जिन पर वह इस तरह की फिर से गिनती की मांग करता है। यह नियम. 63 (2) का प्रभाव है। इन सभी प्रक्रियाओं द्वारा गुजरने के बाद, निर्वाचन अधिकारी फॉर्म-20 में परिणाम-पत्रक को पूरा करता है और उस पर हस्ताक्षर करता है। एक बार ऐसा करने के बाद, फिर से गिनती के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(7) इससे पहले भी, उच्चतम न्यायालय ने राम सेवक यादव बनाम हुसैन *कामिल किदवई और* अन्य *(2) मामले में इसी तरह* का विचार व्यक्त किया था, वहां यह देखा गया था, "-जांच की प्रक्रिया के हर चरण में और
मतों की गिनती में उम्मीदवार या उसके एजेंटों के पास मतों की गिनती में उपस्थित रहने, निर्वाचन अधिकारी की कार्यवाही को

देखने, किसी भी अस्वीकृत मतों का निरीक्षण करने और फिर से गिनती की मांग करने का अवसर होता है।इसलिए, एक उम्मीदवार जो इस आधार पर चुनाव को चुनौती देना चाहता है कि गिनती के समय मतों का अनुचित स्वागत, इनकार या अस्वीकृति हुई है, उसके पास मतपेटियों की जांच और खोलने और मतों की गिनती के तरीके से खुद को परिचित करने का पर्याप्त अवसर है।उनके पास अस्वीकृत मतपत्रों का निरीक्षण करने और फिर से गिनती की मांग करने का भी अवसर है। यह धारा 83 (1) के प्रावधानों के आलोक में है। जिसके लिए उन भौतिक तथ्यों के संक्षिप्त विवरण की आवश्यकता होती है जिन पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है और उस अवसर के लिए जो एक पराजित उम्मीदवार को देखने की गिनती के समय मिला था और एक पुनर्मूल्यांकन का दावा करने के लिए कि निरीक्षण के लिए आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए।"

(8) इसके अलावा, मतों के निरीक्षण और पुनः गिनती का आदेश देने की शक्ति का उल्लेख करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया था, "निरीक्षण के लिए एक आदेश निश्चित रूप से एक मामले के रूप में नहीं दिया जा सकता है; मतपत्रों की गोपनीयता पर आग्रह को ध्यान **में रखते हुए,** न्यायालय निरीक्षण के लिए एक आदेश देने में उचित होगा बशर्ते दो शर्तें पूरी हों:—

(i) आपत्ति को खारिज करने की याचिका में उन भौतिक तथ्यों का पर्याप्त विवरण है जिन पर याचिकाकर्ता अपने मामले के समर्थन में भरोसा करता है और,

(ii) न्यायाधीशाधिकरण प्रथम दृष्टया *संतुष्ट है* कि विवाद का निर्णय लेने और पक्षों के बीच पूर्ण न्यायाधीश आदेश के लिए मतपत्रों का निरीक्षण आवश्यक है।

लेकिन मतपत्रों के निरीक्षण का आदेश याचिका में की गई अस्पष्ट दलीलों का समर्थन करने के लिए नहीं दिया जा

सकता है, न कि भौतिक तथ्यों द्वारा समर्थित या ऐसी दलीलों का समर्थन करने के लिए सबूत जुटाने के लिए। याचिकाकर्ता के मामले को भौतिक तथ्यों के कथन द्वारा समर्थित सटीकता के साथ निर्धारित किया जाना चाहिए। इस प्रकार अनुरोध किए गए मामले को स्थापित करने के लिए निस्संदेह, यदि न्यायाधीश के हितों की आवश्यकता हो, तो निरीक्षण के लिए एक आदेश दिया जा सकता है। लेकिन केवल यह आरोप कि याचिकाकर्ता को संदेह है या विश्वास है कि मतों का अनुचित स्वागत, इनकार या अस्वीकृति हुई है, निरीक्षण के आदेश का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।"

(9) समय बीतने के साथ, हम चंदा सिंह बनाम चौधरी शिवराम *वर्मा और* अन्य *(3) की ओर मुड़ते हैं, जहां,* मतों के निरीक्षण और पुनः गिनती के आदेश के संबंध में कानूनी स्थिति की पुष्टि करते हुए, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने आशंका व्यक्त की, "यदि मतपत्रों की गिनती में बहुत अधिक बार हस्तक्षेप किया जाता है और अदालतों द्वारा फ़्लिपेंट पुनः गिनती न्यायिक साधन द्वारा से चुनाव प्रणाली के लिए एक नया खतरा पेश किया जाता है।इसके अलावा, मतपत्र की गोपनीयता जो पवित्र है, हानिकारक प्रार्थना के लिए उजागर हो जाती है यदि मतों की फिर से गिनती को आसान बनाया जाता है। सामान्य प्रतिक्रिया, यदि इस मुद्दे पर न्यायिक छूट दी जाती है, तो भाग्यहीन उम्मीदवारों पर एक नया दबाव हो सकता है, विशेष रूप से जब जीत का अंतर केवल कुछ सौ मतों का हो।

(10) **यहाँ, मतपत्रों** की अवैध अस्वीकृति या स्वागत की संभावना की खोज के लिए संख्यात्मक रूप से अच्छे भाग्य या अप्रत्याशित रूप से पुनः गिनती के लिए पूछना।यह एक खतरनाक भटकाव की ओर प्रवृत्त हो सकता है जो घोषित रिटर्न को फिर से खोलने के लिए व्यापक गुंजाइश पैदा करके लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला करता है, जब तक कि अदालत

गलत या अवैधता या न्यायाधीश की अन्य मजबूरियों की वास्तविक आशंका के मामलों में फिर से गिनती आदेश के लिए सहारा लेने पर प्रतिबंध नहीं लगाती है, जिसके लिए इस तरह के कठोर कदम की आवश्यकता होती है।

(11) इसी संदर्भ में उठाए गए मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिए और निर्णय लिया जाना चाहिए।

(12) शुरू में ही, लौटे उम्मीदवार द्वारा इस आशय की प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी कि याचिका में किए गए कथन अस्पष्ट थे और उनमें भौतिक तथ्यों का अभाव था और वाद हेतुक किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया गया था। एक याचिका भी दायर की गई थी कि चुनाव याचिका का ठीक से सत्यापन नहीं किया गया था। तदनुसार, दो प्रारंभिक मुद्दे तैयार किए गए थे। ये हैंः—

(1) क्या याचिका दस्तावेज वाद हेतुक किसी भी कारण का खुलासा नहीं करते हैं और याचिका के पैराग्राफ 5 से 9 और 16 और 17 में किए गए कथनों में भौतिक तथ्यों की कमी है। यदि **हाँ, तो इसका क्या प्रभाव होगा?**

(2) क्या चुनाव याचिका का ठीक से सत्यापन किया गया है। यदि नहीं, तो इसका क्या प्रभाव होगा?

याचिका के सत्यापन से संबंधित मुद्दों पर जोर नहीं दिया गया। इस प्रकार विवादित मुद्दा केवल इस संबंध में था कि याचिका में वाद हेतुक कारण का खुलासा किया गया है या नहीं?

(13) जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित मामला यह है कि गिनती की मेजें कांटेदार तार के बाड़े में स्थित थीं और उम्मीदवारों के गिनती एजेंट **गिनती की** मेज से 7 से 10 फीट की दूरी पर थे और इसलिए, गिनती एजेंटों के लिए गिनती की निगरानी करना संभव नहीं था।

(14) यह तीन अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं।सभी चुनाव लड़ने वाले दलों के गिनती एजेंटों के लिए गिनती निश्चित रूप से समान थी और किसी भी उम्मीदवार या उनके एजेंट द्वारा इसके बारे में कोई विरोध या आपत्ति उठाए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए यह आधार अपने आप में मतों की फिर से गिनती के लिए कोई अवसर प्रदान नहीं कर सकता है।

(15) बारीकियों की ओर मुड़ते हुए, तालिका संख्या 1 के संबंध में उद्धृत उदाहरण यह था कि अमर नाथ, एक निर्दलीय उम्मीदवार-कंवर भान के गिनती एजेंट, ने प्रतिवादी-सुरिंदर कुमार के बंडल में याचिकाकर्ता के कुछ वोट देखे। जब उन्होंने इस पर आपत्ति जताई, तो गिनती पर्यवेक्षक ने सुरिंदर कुमार के इन वोटों को ले लिया और उन्हें अमान्य घोषित कर दिया और फिर इन्हें खारिज कर दिया गया।यह कहा गया था कि याचिकाकर्ता के पक्ष में मतपत्र पर एक स्पष्ट निशान था, जिसमें प्रतिवादी सुरिंदर कुमार के प्रतीक पर केवल थोड़ी स्याही का निशान भी था।

(16) इन आरोपों को पढ़ने से पता चलता है कि वे अस्पष्ट हैं और उनमें भौतिक विवरणों की कमी है।ऐसे मतों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही वास्तव में ऐसे किसी भी अस्वीकृत मत की क्रम संख्या का उल्लेख किया गया है।

(17) गिनती के संबंध में इसी तरह के आरोपों का उल्लेख तालिका-2 में मिलता है। यह कहा गया था कि अक्सर याचिकाकर्ता और अन्य उम्मीदवारों के वोट प्रतिवादी-सुरिंदर कुमार के बंडल में पाए जाते थे और जब लगातार मांगों पर, इस प्रतिवादी के बंडल की जांच की जाती थी, तो याचिकाकर्ता और अन्य उम्मीदवारों के वोट निकाल लिए जाते थे और अमान्य घोषित कर दिए जाते थे। इस संबंध में आगे कहा गया कि गणना अभिकर्ता ऐसे मतों की सटीक संख्या को ध्यान दें करने में असमर्थ थे क्योंकि उन्हें अपने साथ कोई लेखन सामग्री ले जाने की

अनुमति नहीं थी।

(18) यहाँ भी, यह देखा जाएगा कि याचिका में दिए गए विवरणों में भौतिक विवरणों की स्पष्ट रूप से कमी है। न तो ऐसे मतों की संख्या का उल्लेख मिलता है और न ही उनकी मतपत्र संख्या का। यह भी ध्यान देने योग्य है कि याचिका में किसी भी उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा गिनती के दौरान किसी भी समय इस दलील की पुष्टि करने के लिए किसी भी आपत्ति का ध्यान दें नहीं किया गया है कि उन्हें गणना कक्ष में सामग्री ले जाने और लिखने की अनुमति नहीं थी और इस प्रकार वे ऐसे मतों के विवरण को नोट करने में असमर्थ थे। किसी भी तरह से, यह आरोप जांच के दायरे में नहीं आ सकता है जब आवेदन अनुलग्नक पी/2 और पी/3 को ध्यान में रखा जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे उसी दिन गिनती के दौरान निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किए गए थे। ये स्पष्ट रूप से उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जा सकते थे और उनके एजेंटों को लेखन सामग्री और कागज से वंचित कर दिया गया था।

(19) मामले का एक पहलू, जो भौतिक महत्व का है और प्रासंगिक है, न केवल पहले संदर्भित आरोपों से निपटने के लिए, बल्कि वर्तमान में जिन पर ध्यान दिया जाना है, वह यह है कि गिनती की प्रक्रिया के अनुसार, मतों की अस्वीकृति हुई, दूसरा तब गिनती की मेज पर। यह या तो निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया गया था और यह माना जाता है कि वह अपने साथ उम्मीदवारों के एजेंटों को बैठेगा, जिन्हें विवादित मतपत्रों की जांच करने का अवसर प्रदान किया जाता है।

इस आशय का कोई दावा नहीं है कि किसी भी प्रश्न या अस्वीकृत मतपत्र के संबंध में इस तरह के अवसर से कभी इनकार किया गया था या उम्मीदवार या उनके एजेंट ऐसे मतपत्रों के विवरण को

नोट करने में असमर्थ थे।

(20) गिनती के दौरान अनियमितताओं के आरोपों की ओर लौटते हुए, गिनती की मेज-3 पर हुई घटनाओं का संदर्भ दिया गया। यहाँ फिर से कहा गया है कि याचिकाकर्ता के कुछ मत सुरिंदर कुमार के बंडल में शामिल किए गए थे और जब यह बताया गया था, तो याचिकाकर्ता के ऐसे मतों को इस आधार पर अमान्य घोषित कर दिया गया था कि हालाँकि निशान याचिकाकर्ता के नाम पर था, लेकिन प्रतिवादी के नाम के सामने मामूली स्याही का निशान भी था। एक बार फिर, ऐसे मतपत्रों का कोई विवरण सामने नहीं आ रहा है।

(21) इसके अलावा, यह माना गया कि चौथे दौर तक गिनती सुचारू रूप से जारी रही, लेकिन जब इसके बाद परिणाम आने लगे कि कांग्रेस (आई) राज्य में कई सीटों पर आगे चल रही थी, तो गिनती अधिकारियों के रूप में काम कर रहे सरकारी अधिकारियों का पूरा रवैया बदल गया और उन्होंने याचिकाकर्ता के पक्ष में डाले गए मतपत्रों को भी अस्वीकार करना शुरू कर दिया। याचिका में ऐसे मतों का कोई विवरण नहीं मिलता है।

(22) इसके बाद, यह कहा गया कि चार दौर की गिनती पूरी होने के बाद, 56 बूथों के मतपत्रों की गिनती की गई थी, लेकिन आधिकारिक संस्करण के अनुसार, 57 बूथों के मतों की गिनती की गई थी। आरोप है कि 43-ए के मतों की कभी गिनती नहीं की गई थी।

(23) 43-ए की गिनती के संबंध में अभिकथन प्रतिवादी द्वारा दायर रिटर्न में विरोधाभासी है जहां यह अनुमान लगाया गया है कि याचिकाकर्ता को 52 वोट मिले जबकि प्रतिवादी ने इस बूथ से 58 वोट हासिल किए और इन वोटों को विधिवत उनके खाते में जमा किया गया।

आगे बढ़ने से पहले, याचिका में एक स्पष्ट चूक यहाँ देखी जा सकती है, अर्थात्; यह आरोप नहीं लगाया गया है कि चुनाव का परिणाम गिनती के दौरान सभी या किसी भी कथित अनियमितताओं से भौतिक रूप से प्रभावित हुआ था। इस संदर्भ में मतदान केंद्र 43-ए के संबंध में किए गए कथन, सही होने पर भी, सफल उम्मीदवार के चुनाव को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है।

(24) इसी तरह, तालिका 4,5 और 6 पर गिनती से संबंधित आरोप हैं, अर्थात्; कि याचिकाकर्ता के मतों की गिनती प्रतिवादी के मतों में की गई थी और जब आपत्ति उठाई गई थी, तो ऐसे मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया था और ऐसी आपत्तियां उठाने वाले व्यक्तियों को धमकी दी गई थी कि उन्हें गिनती कक्ष से हटा दिया जाएगा। यहाँ फिर से, इस तरह के वोटों का कोई विवरण सामने नहीं आ रहा है।

(25) टेबल 7,8,9,10,11,12,13 और 14 पर गिनती के संबंध में इसी तरह के आरोप दोहराए जाते हैं और वे भी उन्हीं दुर्बलताओं से पीड़ित हैं।

(26) अंत में, यह आरोप है कि डाक मतपत्रों की गिनती दो बार लौटे उम्मीदवार के पक्ष में की गई थी। इस कथन में भी भौतिक विवरणों की कमी है, क्योंकि न तो ऐसे मतों की संख्या दी गई है, जैसा कि कहा जाता है कि दो बार गिने गए हैं और न ही ऐसे मतपत्रों का कोई विवरण दिया गया है।

(27) इसलिए यह देखा जाएगा कि याचिका को पढ़ने पर जो बात इतनी प्रमुखता से सामने आती है, वह है याचिकाकर्ता के पक्ष में डाले गए मतों के अस्पष्ट और सामान्य आरोप, जिन्हें पहले लौटे उम्मीदवार के मतों में शामिल किया जाता है और जब उस पर आपत्ति उठाई जाती है, तो ऐसे मतों को अमान्य घोषित किया जाता

है।मान लीजिए, ऐसे किसी भी अस्वीकृत मत का कोई रिकॉर्ड या नोट कभी नहीं रखा गया था। यह दलील कि उम्मीदवारों और उनके एजेंटों को उनके साथ लेखन सामग्री रखने की अनुमति से वंचित कर दिया गया था, विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए बहुत दूर की बात है, विशेष रूप से आवेदन अनुलग्नक पी/2 और पी/3 के संदर्भ में, जो गिनती के दौरान निर्वाचन अधिकारी को स्वीकार किए गए थे। याचिकाकर्ता ने इस कथन की पुष्टि करने के लिए किसी भी सामग्री रिकॉर्ड को स्वीकार नहीं किया है।इसके अलावा और अधिक महत्वपूर्ण यह है कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा विवादित मतपत्रों की जांच के चरण में किसी भी गलत काम के किसी भी दावे का पूर्ण अभाव है, जब उसे यह तय करने की आवश्यकता थी कि मतपत्र वैध था या की अनुपस्थिति में या अस्वीकार किए जाने के योग्य था। कम से कम उस स्तर पर उम्मीदवारों या उनके एजेंटों को मतों की जांच करने के अवसर से इनकार करने का कोई उल्लेख नहीं है। इन सब के अलावा, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इस बात का कोई प्रमाण **नहीं** है कि याचिका में कथित अनियमितताओं से चुनाव का परिणाम **भौतिक रूप से प्रभावित** हुआ था।

(28)पुनःगणतरी के आदेश को उचित ठहराने के लिए भौतिक तथ्यों और विवरणों का अभाव बहुत बड़ा है और ऐसा होने के कारण, इस निष्कर्ष से बचा नहीं जा सकता है कि याचिका वाद हेतुक किसी कारण का खुलासा नहीं करती है, और इसके परिणामस्वरूप रुपये के साथ खारिज कर दिया जाता है। 2, 000 लागत के रूप में।

जे. एस. के.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और

किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

प्रांशु जैन
प्रशिक्षु न्यायिक
अधिकारी,
गुरुग्राम, हरियाणा ।